INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

ISSN: 2230-7850
IMPACT FACTOR : 4.1625(UIF)
VOLUME - 6 | ISSUE - 12 | JANUARY – 2017

महिला सशक्तीकरण में उच्च शिक्षा की भूमिका

प्रिया कुमारी
एम. ए., (समाजशास्त्र),
शोध छात्रा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा.

भूमिका

भविष्य का ज्ञान ज्ञान नेतृत्व के लिए कहता है। भारत आज एक बड़ी शिक्षित जनशक्ति को बढ़ावा दे सकता है, जो किसी भी राष्ट्र के सामाजिकआर्थिक विकास के लिए - कल एक पत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण शिक्षा भारत को तैयार करेगा। शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और समावेशिता राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का कारण है, लेकिन ग्रामीण भारत में यह अधिक गंभीर है। सरकार को उत्पादक कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। शिक्षा महिलाओं खासकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में सक्षम है। यह अंततः लैंगिक समानता की ओर ले जाता है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने का एक मामूली प्रयास किया गया है।

भारत आज एक बड़ी शिक्षित जनशक्ति का दावा कर सकता है, जो किसी भी राष्ट्र के सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साधनों और संसाधनों की गंभीर बाधा के बावजूद, पिछले 66 वर्षों के दौरान देश ने शिक्षा की एक बहुत बड़ी प्रणाली का निर्माण किया है और यह भी कि वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं, मजबूत मानवतावाद, दार्शनिक विचार और के उच्च क्रम से लैस पुरुषों और महिलाओं का एक विशाल पूल रचनात्मकता। 1950 में, हमारे पास केवल एक लाख छात्रों के नामांकन के साथ 25 विश्वविद्यालय और 700 कॉलेज थे। हम उच्च शिक्षा में सभी तक पहुंचके लिए अभिजात्य वर्ग से दूर चले गए हैं। आज, हमारे पास 600 विश्वविद्यालयों और 34,000 से अधिक कॉलेजों में 20 मिलियन छात्र हैं।

भारत, हालांकि, अपने लोगों के समग्र शैक्षिक प्राप्ति के संदर्भ में अपने वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों के साथ अनुकूल तुलना नहीं करता है। यहां तक कि भारत की तुलना में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय कम है, शिक्षा में सकल नामांकन दर (जीईआर) अधिक है। माध्यमिक क्षेत्र में भारत का जीईआर 40% है, पूर्वी एशिया में 70% और लैटिन अमेरिका में 82% है। उच्च शिक्षा में जीईआर लगभग 18.08% है, जो

एशियाई औसत 23% से भी कम है। 29% है दुनियाका औसत GER। हमने अपने आप को 2020 तक 30% करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह एक विशाल निवेश के लिए संसाधनों और जनशक्ति के संदर्भ में कहता है।

भारत अब संस्थानों की संख्या के मामले में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है और चीन के बाद नामांकन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा है। इतनी बड़ी शैक्षिक प्रणाली को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रबंधित करना वास्तव में आज भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। विस्तार, वैश्वीकरण और निजीकरण की मांगों के साथ युग्मित, स्वतंत्रता के बाद बनाए गए संस्थागत ढांचे को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। देश को वास्तव में वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था 'में बदलने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों को शुरू करने की महत्वाकांक्षा के एजेंडे को अपनाया है।

एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण

आज उच्च शिक्षा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि वित्त और प्रबंधन, पहुंच इक्विटी, प्रासंगिकता और नीतियों और कार्यक्रमों के मूल्यों और नैतिकता पर जोर देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्संयोजन, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थानों के मूल्यांकन के साथ मिलकर उनकी मान्यता। ये मुद्दे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। चूंकि उच्च शिक्षा भविष्य के लिए ज्ञान आधारित समाज बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की चुनौती की विशालता छात्रों की बढ़ती संख्या को क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन को दुरुस्त करने, संस्थानों को फिर से मजबूत करने, उत्कृष्टता के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पार करने और ज्ञान के मोर्चे को विस्तारित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। आवश्यकता को पहचानने के साथ- हैं पड़ती निभानी भूमिकाएं की तरह कई को संस्थानों के शिक्षा उच्च कि है यह तथ्य मूल साथ

- नया ज्ञान पैदा करना
- नई क्षमताओं का अधिग्रहण और
- एक बुद्धिमान मानव संसाधन पूल का निर्माण।

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को चैनलाइज़ करके और ज़रूरत और माँग के बीच सही संतुलन बनाए रखते हुए वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कोसना पड़ता है।

- हमें स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखना होगा।
- हमें आजीवन सीखने के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को जुटाना होगा
- हमें एक महत्वपूर्ण सभ्य समाज की नींव रखने में मदद करनी चाहिए
- हमें देश के लिए आवश्यक श्रम शक्ति को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है
- हमें उद्योग और सामाजिक पुनर्निर्माण की जरूरतों के साथ अनुसंधान और प्रशिक्षण को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

दुर्भाग्य से, उच्च शिक्षा ने लक्षित लक्ष्यों, उद्देश्यों और विचारों को पूरी तरह से हासिल नहीं किया है। इसलिए, उच्च शिक्षा क्षेत्र में सफलता का ज्यादा दावा करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी ओर, उच्च शिक्षा ने लोगों को आकर्षक और सफेद कॉलर वाली नौकरियों की तलाश करने के लिए बनाया है। उच्च शिक्षा के उत्पाद उत्पादक रोजगार लेने के इच्छुक नहीं हैं। भारत की उच्च शिक्षा ने कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का हल नहीं खोजा है, जो बहुत ही खतरनाक है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा की दस बीमारियों का निदान किया है:

I. आउटकरिकुलम डेटेड-, समय के साथ तालमेल नहीं रखा;
II. सीखना समझने के बजाय स्मृति पर प्रीमियम रखता है;
III. वर्ग से परे किसी भी चीज के लिए मील का पत्थर अनुकूल नहीं है;
IV. शैक्षणिक कैलेंडर अब कक्षाओं या परीक्षाओं के लिए पवित्र नहीं है:
V. अवसंरचना पतन के कगार पर है;
VI. विषयों के बीच की सीमाएं; विभाजित दीवारें 'बन गई हैं;
VII. अनुसंधान का महत्व समाप्त हो गया है;
VIII. अनुसंधान की मात्रा में गिरावट गुणवत्ता की अनुसंधान और (आवृत्ति की प्रकाशन);
IX. थोड़ी जवाबदेही कोई लिए के प्रदर्शन -पुरस्कार नहीं और गैरनहीं दंड कोई लिए के प्रदर्शन-;
X. बदलते समय और परिस्थितियों के लिए शासन संरचना उत्तरदायी नहीं है कि सिस्टम निहित स्वार्थों द्वारा आसानी से विकृत हो गया है।

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। इस जनसंख्या का तीन चौथाई हिस्सा देश की ताकत बन सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी। मोरा ग्रामीण भारत सीखता है और अपने कौशल को तेज करता है, यह अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा। साक्षर और शिक्षित ग्रामीण भारतीयों के साथ, हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि गांवों की प्रगति बहुत अधिक लागू न हो। ग्रामीण शिक्षा भारत को बेहतर कल के लिए तैयार करेगी। शिक्षा व्यक्ति को व्यापक दृष्टिकोण के साथ समाज और उसके पहलुओं को देखने में सक्षम बनाती है। शिक्षा के बिना, लोग आवश्यक मूल भावना को विकसित करने में असमर्थ हैं। गांवों में रहने वाले लोग 'वास्तविक भारत' की वास्तविक छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत 6 लाख से अधिक गांवों का देश है जहां भारत की आत्मा रहती है। जनगणना 2011 के अनंतिम परिणामों के अनुसार ग्रामीण आबादी का अनुपात कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत है। इस प्रकार, विकास प्रक्रिया में दो तिहाई आबादी को उलझाए बिना टिकाऊ विकास हासिल नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर क्रमशः 68.9 1% और 84.98% है। भारत में पुरुष और महिला की साक्षरता दर क्रमशः 82.14% और 65.46% है जबकि ग्रामीण भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 78.57% और 58.75% है। हम देख सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी शिक्षा का अंतर बहुत अधिक है और ग्रामीण पुरुष और महिला साक्षरता में महत्वपूर्ण अंतर है। इस प्रकार यदि भारत तेजी से समावेशी विकास की परिकल्पना करता है, तो जनसंख्या के इस बड़े हिस्से को विकास प्रक्रिया में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए, अन्यथा यह व्यायाम वांछित फल नहीं देगा, इस संबंध में शिक्षा ग्रामीण विकास की सगाई के लिए सबसे प्रासंगिक तरीका है कि उन्हें विकास की प्रक्रिया में ले जाया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और समावेशिता राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का कारण है, लेकिन ग्रामीण भारत में यह अधिक गंभीर है।

संयुक्त राष्ट्र से सराहना पाने और महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए बहुत कम हासिल करने के बावजूद, पुरुषों की तुलना में कई मामलों में अभी भी एक व्यापक अंतर मौजूद है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को परिवार में उनके अधिकारों, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता तक पहुंच, परिवार के मामलों में और सभी स्वामित्व मुद्दों से ऊपर से इनकार किया जा रहा है और परिणामस्वरूप वे हमेशा परिवार में उपेक्षा महसूस करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होती हैं तो वे न केवल अपने परिवार में बल्कि पूरे समाज

में बदलाव लाने की प्रबल शक्ति बन जाती हैं। लेकिन उस समय की पीड़ा यह है कि हमारे मन में जो असमानता है वह महिलाओं के लिए अपनी क्षमता को पूरा करना मुश्किल बना देती है और परिणामस्वरूप महिलाओं को उन संसाधनों तक शायद ही पहुंचहोती है जो उनके काम को अधिक उत्पादक बनाते हैं और उनके काम का बोझ कम करते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की कमी है और बेहतर प्रदर्शन के लिए ज्ञान हासिल करने के लिए शिक्षा महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन हो सकता है। यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक गाँव में कुछ केंद्र होना चाहिए जो न केवल युवा महिलाओं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान कर सके। शैक्षिक रूप से सशक्त ग्रामीण महिलाएं न केवल अपने स्वयं के आर्थिक विकास में बल्कि देश के समग्र विकास में अधिक योगदान दे सकती हैं। सतत विकास आज और भविष्य के लिए संसाधनों के समान वितरण पर निर्भर करता है। इसे लैंगिक समानता के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कारक है।

सरकारी पहल

सामुदायिक कॉलेजों की स्थापना, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। इन पहलों के कार्यान्वयन से देश में शिक्षा प्रणाली के व्यावसायिककरण में मदद मिलेगी। यह सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल भारतीय जनशक्ति की क्षमता का निर्माण और निर्माण करेगा। ग्यारहवीं योजना में प्रमुख पहल भारत सरकार ने की

- 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रत्येक से जिनमें -16 राज्यों में से एक को शामिल किया गया है, अब तक खुला नहीं है;
- यूजीसी अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले 6000 कॉलेजों और 150 विश्वविद्यालयों को मजबूत करना; • 373 नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना;
- 200 राज्य तकनीकी संस्थानों का विस्तार और उन्नयन:
- 7 विश्वविद्यालयों के तकनीकी संस्थानों उन्नयन का विभाग /;
- 8 नए आईआईटी; 7 नए एलआईएम; 5 आईआईएसईआर, 2 एसपीए;
- 20 नए आईआईटी में मोड पीपीपी हो संभव तक जहां -;
- 10 नए एनआईटी;
- सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 50 केंद्र;
- मौजूदा IlTs और IIM की क्षमता में 200% की वृद्धि।
- मौजूदा पॉलिटेक्निक का सुदृढ़ीकरण,
- 1000 नए पॉलिटेक्निक द्वारा सरकार राज्य -300, पीपीपी मोड में 300, प्राइवेट द्वारा 300।
- 50,000 कौशल विकास केंद्र;
- आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन;
- बढ़ते राज्य सरकार। मौजूदा और नए विश्वविद्यालयों लिए के उन्नयन / विस्तार के संस्थानों व्यावसायिक /;
- उच्च और तकनीकी शिक्षा में ग्रेटर पब्लिक और निजी क्षेत्र का इंटरफ़ेस;
- विदेशी सहयोग, द्विपक्षीय समझौते और गुणवत्ता वाले विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के लिए दरवाजे खोलना।

उच्च शिक्षा के लिए अपनी विभिन्न पहल और योजनाओं का समर्थन करने के लिए, भारत सरकार ने 12 वीं योजना में कई पहल की हैं, अर्थात् 2020 तक उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 30% करना और अन्य कारकों के साथ पीपीपी मॉडल के संचालन के लिए एक जोर दिया है।

कॉरपोरेट सेक्टर की भागीदारी सुनिश्चित करना

उच्च शिक्षा में प्रमुख हितधारक के रूप में कॉर्पोरेट क्षेत्र हमारी वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के साथ के प्रतिबद्धता की पोषण वित्त है। सकता निभा भूमिका महत्वपूर्ण में करने पूरा को आकांक्षाओं की भविष्य साथ-:हैं सकते कर सहयोग साथ के शिक्षाविदों से तरीकों कई निगम साथ

- संस्थानों का प्रत्यक्ष स्वामित्व और प्रबंधन
- अनुसंधान, संकाय विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण, छात्र छात्रवृत्ति और शासन में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग करना।

हालांकि सरकार भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के एक चुनिंदा समूह को विश्व स्तर के संस्थानों में बदलने और वर्तमान मानदंडों को आसान बनाने, प्रणालीगत चुनौतियों पर काबू पाने, उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल बनाने और गुणवत्ता की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करके नए संस्थानों के लिए निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर सकती है। संस्थानों और परिणामों छात्रों), अनुसंधान उत्पादन(, कुछ मुद्दों को कॉर्पोरेट क्षेत्र से उत्पादक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। सरकार को उच्च शिक्षा प्रदाता के रूप में खुद को उच्च शिक्षा के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने के लिए एक उपयुक्त विनियामक ढांचे को सक्षम और स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है:

- उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और
- निवेश आकर्षित करने के लिए उपयोगी।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी के साथ अनुसंधान और संकाय विकास पर ध्यान केंद्रित करके उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
- मौजूदा संस्थानों में निवेश करने, नए संस्थान स्थापित करने और नए ज्ञान समूहों को विकसित करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र को संलग्न करें।

निष्कर्ष

शिक्षा किसी देश के सामाजिक का राष्ट्र एक है। साधन शक्तिशाली एक लिए के विकास और विकास आर्थिक- उसकी विकासशैक्षिक प्रणाली पर बड़े पैमाने पर निर्भर है। हमने गरीबी को कम करने और सभी नागरिकों के जीवन को छूने वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए उच्च आर्थिक विकास की रणनीति अपनाई है। हमारी आर्थिक प्रगति हमारे ज्ञान के आधारों पर तेजी से निर्भर करेगी। वितरणात्मक न्याय, लोकतांत्रिक राजनीति के एक उच्च लक्ष्य के रूप में, एक ध्वनि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भारत की जनसांख्यिकीय संरचना बदल रही है, और 2025 तक, दोला से परिवर्तन इस है। उम्मीद की आने में श्रेणी की करने काम के भारतीयों अधिक से तिहाई-भ उठाने के लिए, हमारे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार होना चाहिए। न केवल भारतीय संदर्भ में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र उत्तर है।

यह वैश्विक परिदृश्य है जिसमें हम रहते हैं। इस परिदृश्य में, अंतिम विश्लेषण में, हमें एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना होगा। जब तक हम ज्ञान में निवेश नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। शिक्षा ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। यह उच्च

समय है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के लिए बेंचमार्क करें। हमें दुनिया को व्यापक बनाने वाले नए प्रतिमानों और प्रथाओं से सीखने की जरूरत है।

संदर्भ:

1. अग्रवाल, पवन (2009), भारतीय उच्च शिक्षा: भविष्य की कल्पना करते हुए, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. मौलिक, बरना)2013), ग्रामीण लोगों के लिए शिक्षाएक लिए के विकास सतत - महत्वपूर्ण कारक, कुरुक्षेत्र, खंड 6, नंबर 11
3. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट, 2007।
4. शंकर दीपा)2010), भारत में शिक्षा क्षेत्रप्रगति :, चुनौतियां और रास्ता आगे, योजनामासिक विकास एक -, वॉल्यूम। 54, जनवरी
5. शर्मा, अजय पाल)2013), ग्रामीण महिला सशक्तिकरणदृष्टिकोण विश्लेषणात्मक एक -, कुरुक्षेत्र, खंड 6, संख्या 10
6. सिब्बल, कपिल)2011), द इमर्जिंग परिदृश्य इन एजुकेशन, नानी ए पलखीवाला मेमोरियल ट्रस्ट, मुंबई।
7. ताज, हसीन)2008), शिक्षा में वर्तमान चुनौतियाँ, नीलकमल प्रकाशन, हैदराबाद।
8. टाइम्स ऑफ इंडिया)2012), व्हाई अवर एजुकेशन सिस्टम फेलिंग, संपादकीय 28 जून, अहमदाबाद।